20th May and not on the 21st May. The demonstrators surrounded the car of the G. M. at the time of his leaving the office and after detaining him for some time, they dispersed after presenting a Memorandum to the General Manager containing several demands relating to the recognition of the dissident group of the Eastern Railwaymen's Union, trade union rights etc. Most of these demands had been examined in the past and not found acceptable. They will continue to be examined on their merits.

Export of Iron Ore to Japan

*415. **Shri Chintamani Panigrahi:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Japanese firms have expressed the desire to pay 15 shillings extra per ton of iron ore, if it is exported from Paradeep Port in Orissa;

(b) if so, the action being taken by Government to increase the iron ore export from Paradeep; and

(c) whether it is a fact that the M.M.T.C. has offered a reduced price to the Japanese firms to accept iron ore from the port like Calcutta?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

कानपुर के औद्योगिक संस्थानों से वसूल किया जाने वाला रेलवे भाड़ा

*416. श्री शिवचरण लाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर के औद्योगिक संस्थानों अर्थात् जुगी लाल कमला पत, लक्ष्मी रतन काटेन मिल्स, ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, म्युर मिल्स आदि औद्योगिक संस्थानों से 1 अप्रैल 1966 तक की अवधि के लिये रेलवे भाड़े तथा इन संस्थानों में रेलवे द्वारा बनाई रेलवे साइडिंग्स की रखरखाव के लिये खर्च के लिये कुल कितनी राशि वसूल करनी शेष है ; और

(ख) इस अत्यधिक बकाया राशि को वसूल करने के लिये रेलवे प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) उल्लिखित फर्मों और कुछ अन्य फर्मों के जिम्मे बकाया भाड़ा और अनुरक्षण प्रभार के सम्बन्ध में एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT.—584/67]

(ख) रेल प्रशासन फर्मों से सम्पर्क स्थापित करता है और पत्र लिख कर निवेदन करता है कि बकाया रकम का भुगतान करें । यदि इससे कोई परिणाम नहीं निकलता तो रेल प्रशासन उन्हें चेतावनी देता है कि यदि एक निश्चित अवधि में बकाया रकम का भुगतान नहीं किया गया तो रेलवे उनके माल को रोक लेगी जिसके सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 55 के अन्तर्गत रेलवे को ग्रहणाधिकार प्राप्त है या साइडिंग में माल डिब्बे पहुंचाना बन्द कर देगी । यदि इस नोटिस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता तो दी गयी चेतावनी पर अमल किया जाता है ।

700 H.P. Diesel Locomotives

*417. **Shri Hem Raj:** Will the Minister of Railways be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the 700 H.P. diesel locomotives have been designed by the Railway Research, Designs and Standards Organisation for the Narrow Gauge Section;

(b) if so, whether their manufacture has been undertaken and at which place; and

(c) by what time these locomotives will be put on the rails on the narrow-gage sections and which narrow-

gauge sections have been selected for this purpose?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes, Sir.

(b) Not yet.

(c) Does not arise at this stage.

इस्पात का उत्पादन

*418. श्री क० मि० मधुकुर : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 के बाद स्वतन्त्र हुए देशों के बीच जिनमें चीन भी शामिल है इस्पात उत्पादन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है ;

(ख) क्या यह सच है कि चीन प्रति वर्ष भारत की अपेक्षा अधिक इस्पात का उत्पादन कर रहा है ; और

(ग) इस्पात के उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिये क्या सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० श्रीमती रेड्डी) : (क) और (ख). चीन के इस्पात के उत्पादन के बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध रिपोर्टों से ऐसा प्रतीत होता है कि क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद आता है ।

(ग) इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्नलिखित योजनाओं पर विचार किया जा रहा है :

(i) भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, टाटा और इंडियन आयरन के इस्पात कारखानों तथा निजी क्षेत्र में बिजली घट्टियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना ।

(ii) बोकारो के अलावा दो नये इस्पात कारखानों की स्थापना ।

(iii) उत्पादन के अधिक अच्छे तरीके अपनाना ।

इसके अतिरिक्त हम इस्पात कारखानों की मशीनें और उपकरण बनाने के काम में आगे बढ़ रहे हैं और जल्दी ही हम बहुत हद तक स्वत: नये कारखाने लगा सकने की स्थिति में हो जायेंगे ।

Monopoly Commission

*419. **Shri R. K. Amin:** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state:

(a) the reasons why the study of undesirable monopoly practices adopted by public sector industries was precluded from the scope of the Monopoly Commission;

(b) whether Government contemplate to appoint another Monopoly Commission to make the study of monopoly practices adopted by the public sector industries;

(c) whether Government contemplate to appoint a commission to study the concentration of power in the hands of big trade unions which enjoy a dominent power over the supply of labour; and

(d) whether Government contemplate to take any significant measures, besides setting up a body as recommended in the Monopoly Commission, to prevent the growth of unhealthy monopoly practices in this country, both in the private sector as well as in the public sector?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) It is not correct to say that the public sector undertakings adopt monopoly practices. Working of the public sector industries is subject to the control of Parliament through its various Committees and hence it was not considered proper to include the public sector industries in the